आद्री
ADRI

प्रकाशनार्थ

पटना, 28 अगस्त। आज एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर द्वारा ''भारत में छोटी जोत वाले किसानों पर कोविड-19 का प्रभाव और भावी दिशाएं'' शीर्षक वेबिनार का आयोजन किया गया। चर्चा में भाग लेने वाले लोगों में बिहार के कृषि विभाग के सचिव श्री एन. श्रवण कुमार, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर सुश्री जे.वी. मीनाक्षी, और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च के निदेशक और उप-कुलपति श्री महेंद्र देव शामिल थे। इसका संचालन आइएफपीआरआइ के सीनियर रिसर्च फेलो श्री अंजनी कुमार ने किया।

प्रोफेसर मीनाक्षी ने पांच राज्यों के कृषि बाजारों पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया और कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा समर्थन कार्य वापस लेने पर भी गेहूं की कीमत स्थिर रही है लेकिन अन्य तीन राज्यों में उसमें गिरावट आई। उनका निष्कर्ष था कि कोविड-19 के कारण कीमतों पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन बाजार में उनकी आवक पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार संबंधी सुधार अपनाना मुख्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए अधिक मायने रखता है।

श्री श्रवण कुमार ने कहा कि महामारी से बिहार में छोटे किसानों की असुरक्षा और अधिक बढ़ गई है। बिहार के टमाटर उपजाने वाले छोटे किसान मांग में कमी आने के कारण अपने शीघ्रनाशी उत्पाद को नहीं बेच सके और उनकी बहुत मदद भी नहीं की जा सकी। दूसरी ओर, तमिलनाडु जैसे राज्य में विपणन स्कंध है और वहां बाजार पाने में वहां के छोटे किसानों की मदद की जा सकी है। उन्होंने रेखांकित किया की महामारी के बाद तीन चीजें आम होने जा रही हैं। कृषक उत्पादक कंपनियां अधिक बड़ी भूमिका निभाएंगी क्योंकि उन्होंने महामारी के दौरान उनलोगों ने बिहार आम और लीची के विपणन की सफलतापूर्वक व्यवस्था की। सरकार को बिहार के सभी जिलों में जलवायु-सक्षम कार्यक्रमों का विस्तार करके छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन का सफलतापूर्वक सामना करना सिखाना होगा। साथ ही, सीबीटी जैसी प्रौद्योगिकियों का भी अधिक उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ''सीमांत और छोटी जोतों वाले किसान इस महामारी में अधिक असुरक्षित हैं और साथ ही हम इस समय टिड्डियों के आक्रमण जैसी जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। जलवायु-सक्षम कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलकदमियां 8 जिलों में शुरू की गई हैं और अभी सभी 38 जिलों में उनका विस्तार किया जा रहा है।''

महेंद्र देव की राय थी कि छोटे किसानों के लिए बड़े किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की गुंजाइश उपलब्ध कराने की जरूरत है। महिला स्वयं सहायता समूहों आदि में संगठित होकर उन्हें अपने उत्पादों को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए ताकि उन्हें सही कीमत मिल सके। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज होने जा रही है जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निकट भविष्य में गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि छोटे खेतों के उत्पादों को एक जगह लाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस महामारी के दौरान किसानों के लिए सही कीमत पाने पर इसका असर पड़ेगा। अतः स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और उनकी कुशलता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

वेबिनार का संचालन करते हुए डॉ. अंजनी कुमार ने कहा कि कोविड-19 संकट के कारण कृषि आपूर्ति शृंखलाओं और कार्यमुक्त हुए श्रमिकों की असुरक्षित स्थिति ने सभी प्रकार की जोतों वाले किसानों को चोट पहुंचाया है- खास कर सीमांत और छोटी जोतों वाले किसान अधिक असुरक्षित हैं।

वेबिनार में आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने कहा कि स्वास्थ्य आपदा के बतौर जारी कोविड-19 ने सभी प्रकार की जीवन-पद्धतियों को प्रभावित किया है। इस महामारी में लोगों की जिंदगी बचाना और महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनो की तत्काल प्राथमिकता है। दोनो सरकारों ने इस आपदा से निपटने के लिए कमर कस ली है और वायरस का संचरण सीमित करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन भी करना पड़ा है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी वक्ता इस का पता करें कि ''छोटी जोतों वाले किसान इस संकट के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और सरकारी उपाय देश के करोड़ों कृषक परिवारों पर कैसा असर डालती हैं'' और उपयुक्त उपाय सुझाएं। आइजीसी के कुमार दास और बिजेता मोहंती ने भी इस आयोजन में भाग लिया।

(अंजनी कुमार वर्मा)

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102